

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक-2025 पेश किया। इसका उद्देश्य ई-खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना है। एक रिपोर्ट—

इस विधेयक में पैसा लेकर ऑनलाइन खेलों की पेशकश करने, संचालन करने या प्रोत्साहन करने पर, पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेम से जुड़े कानून के उल्लंघन पर, तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई, इस कानून का दोबारा उल्लंघन करता है, तो तीन से पांच साल तक की कैद, और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना, हो सकता है। यह विधेयक वित्तीय प्रणाली की अखंडता और देश की सुरक्षा, और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसके अलावा, यह जनहित में एक समान और राष्ट्रीय स्तर का, कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। यह विधेयक देश के युवाओं को, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स जैसे कि पोकर और रम्मी जैसे प्रलोभन वाले गेम से बचाएगा, जो उन्हें आर्थिक लाभ के झूठे वादों के जरिए, फंसाने का काम करते हैं, जिसके कारण पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है। दीपेन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए के उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे पी नड्डा, किरेन रिजिजू तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले श्री राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उप-राष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान नौ सितम्बर को होगा। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच बाइस अगस्त को होगी और पचीस तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। दिक्कत केवल जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले तत्व पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार खाद वितरण पर नजर बनाये हुए है ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। अब तक इग्यारह सौ छानबे फुटकर विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किये जा चुके हैं। एक सौ बत्तीस थोक विक्रेताओं को नोटिस, तेरह का निलम्बन और चार का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। तिरानबे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है। श्री शाही ने बताया कि कार्रवाई के क्रम में सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। वहीं, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गये हैं, जिन्होंने बिना जोत के ही दर्जनों बोरी यूरिया उठा ली। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर किसान को समय से खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिये पूरी तरह सक्रिय है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोलह सितम्बर से फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभाग के अधिकारियों को मानक कार्यप्रणाली उपलब्ध करायी जाय ताकि अधिकार अभिलेख में मालिकों के नाम को आधार के अनुसार सही किया जा सके। प्रदेश में कुल दो करोड़ अट्ठासी लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब पचास प्रतिशत से अधिक किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। फार्मर रजिस्ट्री में अब तक बिजनौर जिला सबसे आगे है, जहां अट्ठावन प्रतिशत रजिस्ट्री हो चुकी है। इसके बाद हरदोई, श्रावस्ती, पीलीभीत और रामपुर प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में शामिल है।

रुक रुककर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद, बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या, तुर्तीपार में घाघरा और शाहजहांपुर में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक रिपोर्ट—

शाहजहांपुर में रामगंगा नदी के किनारे बसे कई गांवों के खेत पानी में डूब गए हैं। जलालाबाद और कलान तहसील के पचास से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे के कई क्षेत्र पानी में डूब गये हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। वहीं अमरोहा में बिजनौर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ग्रामीणों से नदी की ओर नहीं जाने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
